SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों के आय संरचना का अध्ययन

डॉ० कोमल प्रसाद
Ph.D. (Economics), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

शोध सारांश

स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से अब तक गरीबी उपशमन के साधन के रूप में यह सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। वास्तव में लाभ से वंचित लाभार्थियों को भी सहायता मिले और लाभार्थियों को का चयन उद्देश्यपरक एवं जांचे जाने योग्य हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में बीपीएल परिवारों में से लाभार्थियों का चयन करने के बजाय सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में उल्लिखित मकानों की कमी संबंधी मानदण्डों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में हितग्राहियों के आय संरचना का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की आय संरचना का अध्ययन कर योजना की कमियों और विकास को रेखांकित कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत अध्ययन में मुंगेली जिले के विशेष संदर्भ पर आधारित है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी– प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबी उन्मूलन, आय संरचना, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति

प्रस्तावना

मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताएं सदैव से रही है, रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें से आवास जीवन की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो सर्दी, गर्मी और

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

बारिश जैसे मौसमी मार से बचाव हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। विकसित होते समाज में आवास को मानव विकास हेतु एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में अपनी महत्ता दिखाई। इस प्रकार आवास मानव विकास और स्थायित्व का अभिन्न अंग है। इसी श्रृंखला में मानव के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए आवास के महत्व को देखते हुए शासन की ओर से व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा।

देश की आधी आबादी के पास जमीन का मामूली टुकड़ा भी नहीं है जिस पर वह चार दिवार और एक छत बना सके। जिन लोगों के पास आवास है उनमें बड़ी संख्या कच्चे मकानों या झोपड़ियों की है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के बाद भी बेघर और झोपड़ियों में गुजर–बसर करने वाले लोगों की गरीबी व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी अभिशाप होती है। भारत में आवास योजना की नीतियाँ ग्रामीण समाज के अंतर्गत आवास की समस्या को दूर करने हेतु इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने एवं क्रियान्वित करने की महती प्रयास करने की आवश्यकता है।

साहित्य का पुनरावलोकन

1. **मोहन राव कुचिपुड़ी (2015)** ने ''आंध्र प्रदेश में आवास परिदृश्य'' पर अध्ययन किया है। उन्होंने व्यक्तियों के लिए आवास के सामाजिक–आर्थिक महत्व पर जोर दिया और परिवारों की गोपनीयता और जीवन की सुरक्षा के लिए आवास प्रमुख रूप से मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का घटक है आवास की समस्या भारत जैसे विकासशील देशों में तीव्र है। आवास की स्थिति भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद असंतोषजनक है। उनके अध्ययन के आधार पर आंध्रप्रदेश में लेखकों ने निष्कर्ष निकाला है कि आवास की स्थितियां रसोई, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, जल निकासी, बाथरूम सुविधा आदि से संबंधित अनिश्चित लेखकों ने सुझाव दिया है कि लाभार्थियों को घरों की मंजूरी से पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए एक उचित घरेलू सर्वेक्षण करना आवश्यक है राज्य में पक्के मकान की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करना जरूरी बताया है।

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

2. **कल्पना गोपालन और मदालसा वेंकटरमन (2015)** ने अपने लेख में ''भारत में सस्ती आवास में नीति और व्यवहार का अध्ययन'' करना रहा है। उन्होंने तर्क दिया है कि वहनीय आवास एक ऐसी समस्या है जिसका कई देश दुनिया भर में जूझ रहे हैं। लेखकों ने इस तथ्य का हवाला दिया है कि, भारत में समस्या बहुत अधिक गंभीर है। इसमें से 99 प्रतिशत के साथ लगभग 18 मिलियन घरों की अनुमानित कमी है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग समस्या से ग्रस्त हैं। इसके अलावा, उन्होंने राज्यों में किफायती आवास नीतियां बनाना और लागू करने का सुझाव दिया है।

3. **अम्मानया के.के. (2015)** अपने लेख ''भारत में आवास विकास– समस्याएँ, मुद्दे और चुनौतियाँ और उन्हें संबोधित करने के लिए रणनीतियाँ'' है में वृद्धि के बावजूद आवास की कमी को एक गंभीर समस्या माना 2001 में हाउसिंग स्टॉक 24.9 करोड़ से 2011 में 33.1 करोड़ हो गया, इस प्रकार एक दिखा रहा है 33 प्रतिशत की वृद्धि। वर्तमान में उपलब्धता और के बीच एक बेमेल है घरों की वास्तविक आवश्यकता। लेखक ने अनुमानित आवास की कमी का हवाला दिया है 2012–17 में शहरी क्षेत्रों में लगभग 95 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच और निम्न आय वर्ग की श्रेणियाँ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 प्रतिशत है गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में कमी। लेखक ने के लिए सुझाव दिया है आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार उपयुक्त रणनीतियां शुरू करेगी भारत।

4. **साल्वे प्रकाश वनकर और भिसे वी.बी. (2014)** ने ''जालना में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन'' पर जांच की, जिसमें पाया गया कि योजना से ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आईएवाई के लागू होने के बाद से दयनीय स्थिति में रहने वालों के पास है उनके रहने की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। लेखकों ने सुझाव दिया है कि कई लाभार्थियों की निरक्षरता को देखते हुए आईएवाई योजना बनाई जानी चाहिए।

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन प्रतिदर्श अनुसंधान है। न्यादर्शो के चयन हेतु दैव निदर्शन तकनीक का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ होगा किन्तु विस्तृत एवं गहन अध्ययन हेतु मुंगेली जिले में लाभान्वित परिवारों के चयन में निदर्शन प्राविधि को प्रयुक्त किया गया है। अध्ययन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु लाभान्वित परिवारों की सूची प्राप्त की गई जो लाभान्वित परिवारों के साथ ही प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु ऐसे लाभान्वित परिवारों को सम्मिलित किया गया जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की मद से आवास निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है जो चयन का मुख्य आधार है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य लाभान्वित परिवारों के योजना में शामिल होने के पूर्व एवं योजना में शामिल होने के पश्चात् उनकी आय संरचना का विश्लेषण कर अध्ययन करना है।

शोध परिकल्पना

H_0.1– संलग्न परिवारो की दैनिक आय में वृद्धि से उनका आर्थिक विकास हुआ और तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्यविधि महत्वपूर्ण रही है।

H_0.2– योजना में संलग्न परिवारों की आय संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।

आंकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक स्त्रोत (प्राथमिक समंक) पर आधारित है तथा आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया है। शोध में द्वितीय समंक हेतु जिलों में स्थापित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, सरकारी तथा गैर सरकारी बैंक, महिला बाल विकास विभाग आदि के माध्यम से समंकों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासकीय प्रलेखों, प्रतिवेदनों, शोध पत्रों, ग्रंथालय, शोध से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, वेबसाइट्स का उपयोग किया गया है।

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- मुक्त बंधुआ मजदूर
- रिटायर्ड और कार्रवाई में शहीद हुए रक्षा कर्मियों
- अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधवाओं और आश्रित–परिजन
- विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाले लोग

हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति का विवरण

तालिकाः हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	कार्य का प्रकार	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	कुल	प्रतिशत
1.	मजदूरी	67	59	60	186	62
2.	खेती	24	33	29	86	28.67
3.	प्राईवेट नौकरी	4	6	7	17	5.67
4.	सरकारी नौकरी	2	2	1	5	1.67
5.	अन्य	3	0	3	6	2
	योग –	**100**	**100**	**100**	**300**	**100**

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर–दिसंबर, 2022

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के जीवनयापन के लिए कार्य की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान विकासखण्ड लोरमी में 67, विकासखण्ड मुंगेली में 59 तथा विकासखण्ड पथरिया में 60 हितग्राही मजदूरी करते पाए गए तथा विकासखण्ड लोरमी में 24, विकासखण्ड मुंगेली में 33 तथा विकासखण्ड पथरिया में 29 हितग्राही खेती करते पाए गए जबकि विकासखण्ड लोरमी में 4, विकासखण्ड मुंगेली

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

में 6 तथा विकासखण्ड पथरिया में 7 हितग्राही प्राइवेट नौकरी तथा विकासखण्ड लोरमी में 2, विकासखण्ड मुंगेली में 2 तथा विकासखण्ड पथरिया में 1 हितग्राही सरकारी नौकरी करते पाए गए। विकासखण्ड लोरमी में 3 तथा विकासखण्ड पथरिया में 3 हितग्राही ऐसे पाए गए जो अन्य साधनों से रोजगार प्राप्त कर अपना और अपने परिवार का भरणपोषण करते हैं।

इस प्रकार मुंगेली जिले के कुल 300 हितग्राहियों में से 186 (62%) हितग्राही मजदूरी करते पाए गए तथा 86 (28.67%) हितग्राही खेती, 17 (5.67%) हितग्राही प्राइवेट नौकरी तथा 5 (1.67%) हितग्राही सरकारी नौकरी करते पाए गए जबकि 6 (2%) हितग्राही ऐसे पाए गए जो अन्य साधनों से रोजगार प्राप्त करते हैं।

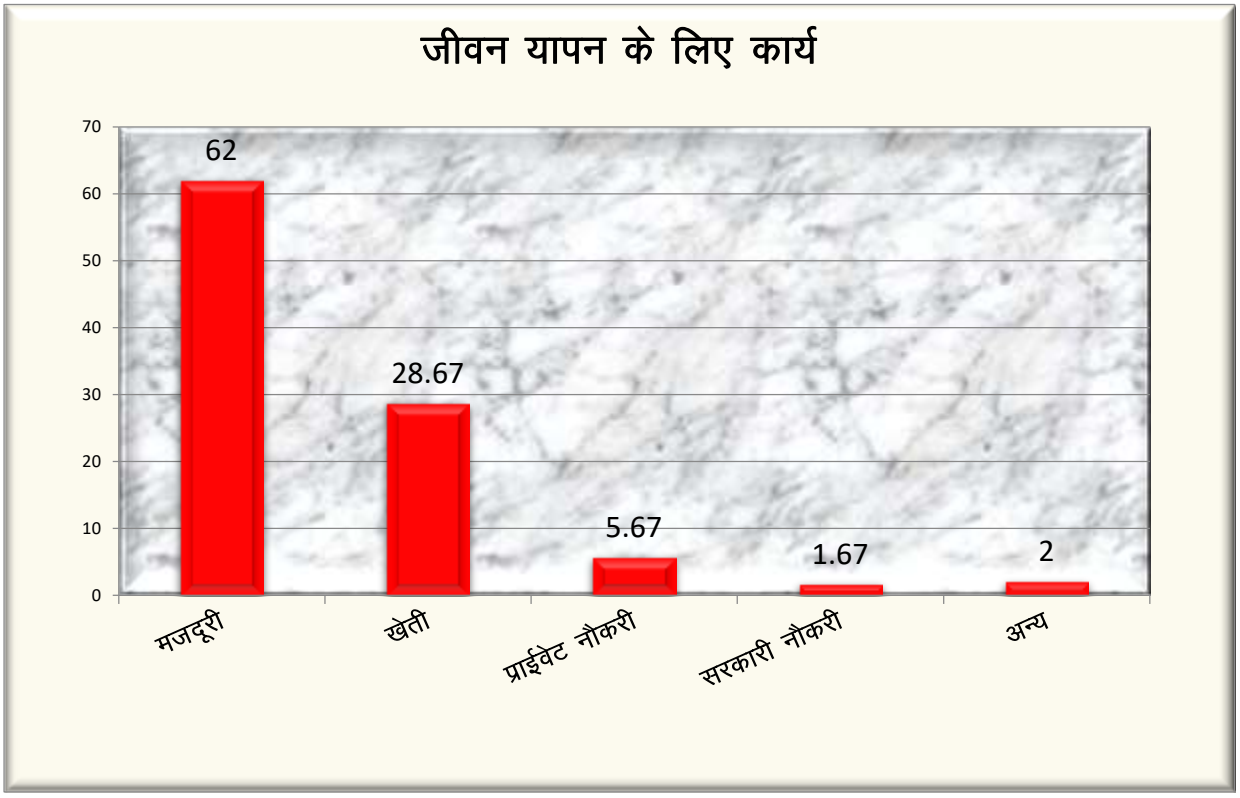

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

आवास में संलग्नता से पूर्व दैनिक आय के स्तर का विवरण

तालिकाः आवास में संलग्नता से पूर्व दैनिक आय के स्तर का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	आवास में संलग्नता से पूर्व दैनिक मजदूरी दर	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	योग	प्रतिशत
1.	100–150	72	59	69	200	66.67
2.	150–200	13	23	19	55	18.33
3.	200–250	4	7	3	14	4.67
4.	250–300	3	3	3	9	3.00
5.	300–350	2	3	2	7	2.33
6.	350–400	3	2	2	7	2.33
7.	400–450	1	2	2	5	1.67
8.	450 से अधिक	2	1	0	3	1.00
	योग :–	**100**	**100**	**100**	**300**	**100.00**

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर–दिसंबर, 2022

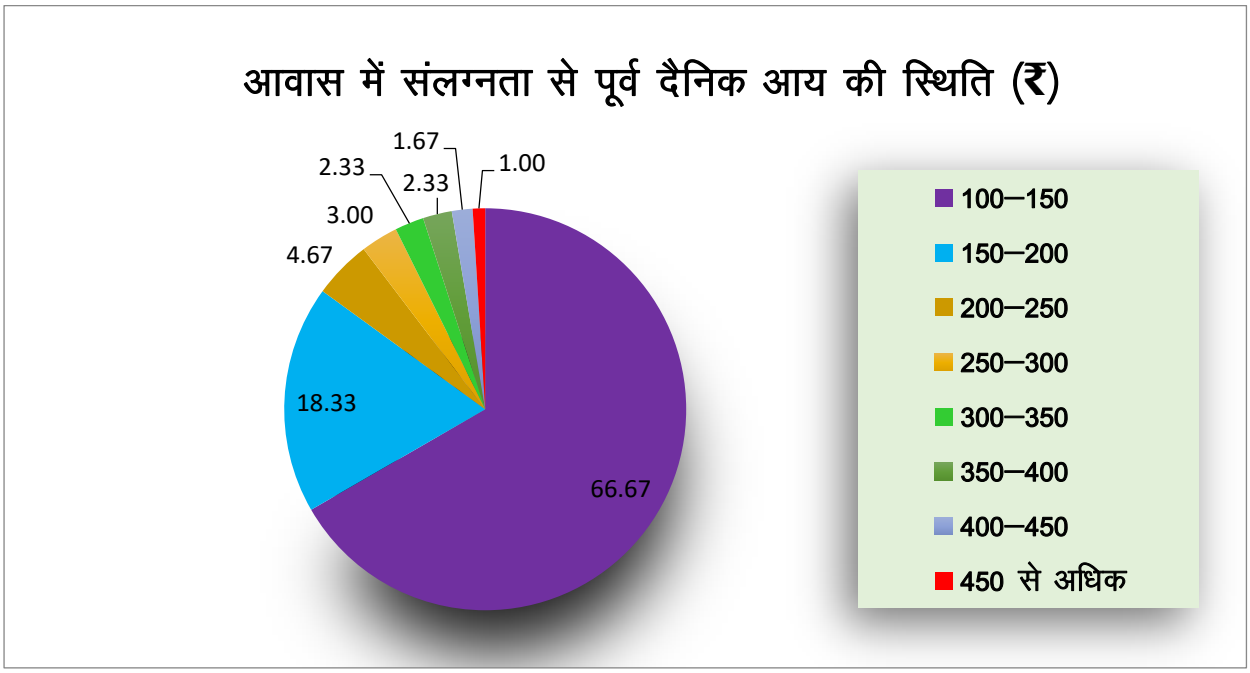

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के आवास में संलग्नता के पूर्व दैनिक आय के स्तर को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान आवास में संलग्नता के पूर्व मुंगेली जिले के कुल 300 हितग्राहियों में से 200 (66.67%) हितग्राही 100–150/– दैनिक मजदूरी दर प्राप्त करते पाए गए तथा 55 (18.33%) हितग्राही 150–200/–, 14 (4.67%) हितग्राही 200–250/–, 9 (3%) हितग्राही 250–300/–, 7 (2.33%) हितग्राही 300–350/–, 7 (2.33%) हितग्राही 350–400/–, 5 (1.67%) हितग्राही 400–450/– तथा 3 (1%) हितग्राही 450 रूपये से अधिक दैनिक मजदूरी दर प्राप्त करते पाए गए।

आवास में संलग्नता के पश्चात् दैनिक आय के स्तर का विवरण

तालिकाः आवास में संलग्नता के पश्चात् दैनिक आय के स्तर का विवरण एवं प्रतिशत

क्र.	आवास में संलग्नता से पूर्व दैनिक मजदूरी दर	लोरमी	मुंगेली	पथरिया	योग	प्रतिशत
1.	100–150	21	14	20	55	18.33
2.	150–200	21	15	20	56	18.67
3.	200–250	10	20	18	48	16.00
4.	250–300	12	15	10	37	12.33
5.	300–350	11	16	12	39	13.00
6.	350–400	10	6	9	25	8.33
7.	400–450	5	9	7	21	7.00
8.	450 से अधिक	10	5	4	19	6.33
	योग :–	**100**	**100**	**100**	**300**	**100.00**

स्त्रोतः– प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर–दिसंबर, 2022

उपर्युक्त तालिका एवं रेखाचित्र में हितग्राहियों के आवास में संलग्नता के पश्चात् दैनिक आय के स्तर को प्रदर्शित किया गया है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान आवास में संलग्नता के पश्चात् मुंगेली जिले के कुल 300 हितग्राहियों में से 55 (18.33%) हितग्राही 100–150/– दैनिक मजदूरी दर प्राप्त करते पाए गए तथा 56 (18.67%) हितग्राही

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

150–200/–, 48 (16%) हितग्राही 200–250/–, 37 (12.33%) हितग्राही 250–300/–, 39 (13%) हितग्राही 300–350/–, 25 (8.33%) हितग्राही 350–400/–, 21 (7%) हितग्राही 400–450/– तथा 19 (6.33%) हितग्राही 450 रूपये से अधिक दैनिक मजदूरी दर प्राप्त करते पाए गए।

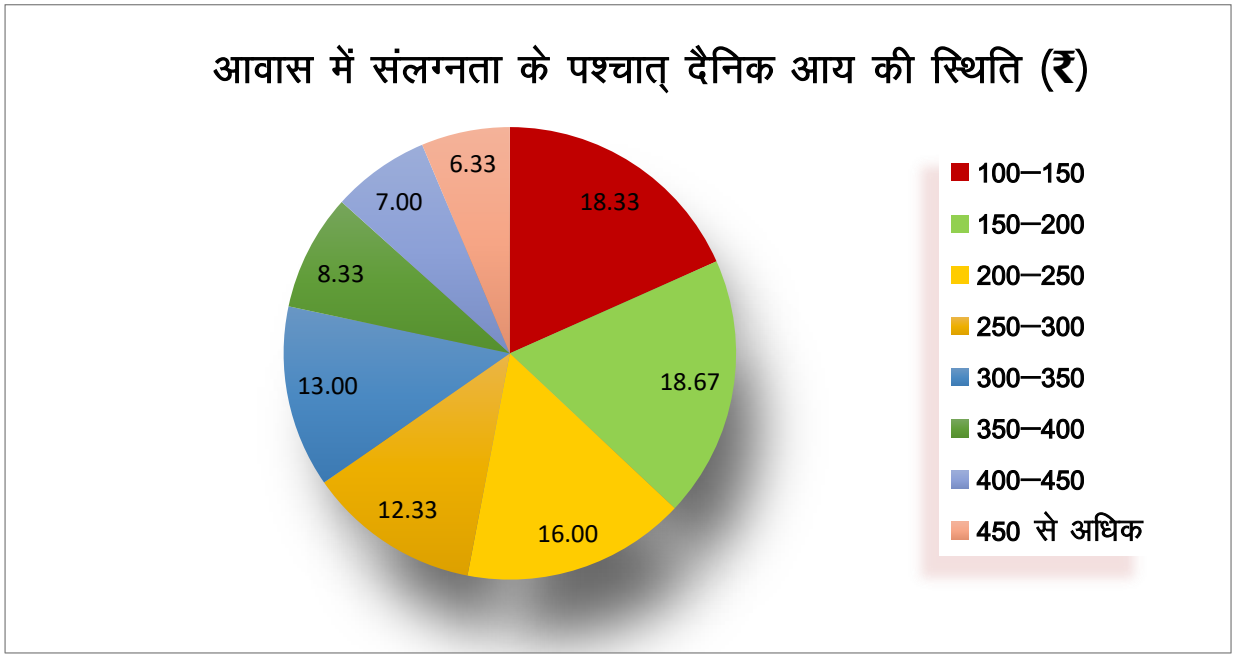

निष्कर्ष

- कुल 300 हितग्राहियों में से सर्वाधिक 186 (62%) हितग्राही जीवनयापन हेतु मजदूरी करते हैं जो कि उनकी आय का मुख्य साधन है जबकि सबसे कम 5 (0.67%) हितग्राही सरकारी नौकरी करते पाए गए हैं।
- कुल 300 हितग्राहियों में से सर्वाधिक 200 (66.67%) हितग्राही ऐसे पाए गए जिनकी आवास में संलग्नता से पूर्व आय न्यूनतम 100–150 रूपये थी जबकि अधिकतम आय 450 रूपये से अधिक प्राप्त करने वाले केवल 3 (1%) हितग्राही पाए गए। पथरिया विकासखण्ड में कोई हितग्राही ऐसे नहीं पाए गए जिनकी आय 450 रूपये से अधिक हो।

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

- कुल 300 हितग्राहियों में से सर्वाधिक 56 (18.67%) हितग्राही ऐसे पाए गए जिनकी आवास में संलग्नता के पश्चातृ आय न्यूनतम 150–200 रूपये पाई गई जबकि अधिकतम आय 450 रूपये से अधिक प्राप्त करने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 19 17 (6.33%) हो गई।

चुनौतियां

- हितग्राहियों के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना 2011 में नाम होने होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे आने वाले बहुत से परिवारों का आवास प्राप्ति से वंचित हो जाना।
- कम आमदनी और कम बचत होने के कारण हितग्राहियों द्वारा समय पर और मनचाहे आवास का न बन पाना।
- पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होना।
- आवास निर्माण के दौरान हितग्राहियों द्वारा दैनिक मजदूरी पर जाने के कारण निर्माण कार्य के उचित देखरेख का अभाव।
- ग्रामीण स्तर पर कुशल कारीगरों तथा संसाधनों का अभाव होने के कारण आवास निर्माण में होने वाले व्यय में वृद्धि।

सुझाव

- सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना, 2011 में पाए गए गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के अतिरिक्त आवासहीन परिवारों को आवास योजना का लाभ देना चाहिए।
- सरकार को इस दिशा में ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि हितग्राहियों को सहीं एवं निश्चित समय पर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जिससे हितग्राहियों को आवास निर्माण के दौरान समस्या न हो जिससे हितग्राहियों द्वारा सुचारू रूप से आवास निर्माण किया जा सके।
- सरकार को आवास निर्माण संबंधी एजेंसी स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम बनाए जाने एवं योजना में पारदर्शिता की आवश्यकता है।

SHODHBODHALAYA (शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 2, Issue 1, October-December 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

- आवास निर्माण के दौरान निर्माण की गुणवत्ता का निर्धारण में पारदर्शिता होनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के भवन निर्माण में लगे कारीगरों को राजमिस्त्री के रूप में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- मोहन राव कुचिपुड़ी (2015) आंध्र प्रदेश में आवास परिदृश्य, दक्षिणी अर्थशास्त्री, 1 अगस्त।
- कल्पना गोपालन और मदालसा वेंकटरमन (2015) खरीदने की सामर्थ्य आवास भारत में नीति और व्यवहार", आई.आई.एम.बी. प्रबंधन समीक्षा, जून।
- अम्मान्नया के.के. (2015)। भारत में आवास विकास – समस्याएं, मुद्दे और चुनौतियाँ और उन्हें संबोधित करने की रणनीतियाँ, दक्षिणी अर्थशास्त्री, 1 अगस्त.
- साल्वे प्रकाश वनकर और भिसे वी.बी. (2014) "सामाजिक–आर्थिक अध्ययन "जालना में इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी", दक्षिणी अर्थशास्त्री, फरवरी।
- माही पाल (2005). पंचायत राज संस्थाएँ और ग्रामीण आवास, कुरूक्षेत्र, खंड. 53, क्रमांक 12, अक्टूबर।
- निर्मल कुमार (2005) ग्रामीण आवास बिहार की समस्याएं, सामाजिक परिवर्तन, वॉल्यूम. 35, क्रमांक 4, दिसंबर।
- Mr. R.M. Ravi (2020) "A Study on the effectiveness of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban in the selected State of India" Ph.D. thesis, University of Tamilnadu.